भारत-ईरान संबंध

- डॉ. अरुण कुमार

पृष्ठभूमि

पश्चिम एशिया की राजनीति का निर्धारक ईरान दुनिया के प्रमुख विकासशील देशों में से एक है। सातवें दशक के अन्त में शाह रजा पहलवी को गद्दी से उतार फेंकने वाला कट्टरपंथी उबाल अब उतार पर है तथा राष्ट्रपति अली अकबर हाशमी रफसनजानी तेल से समृद्ध देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने तथा लगभग एक दशक से अधिक समय तक क्रांति और युद्ध से झुलसते रहे देश को बेहतर जीवन देने के प्रयासों में लगे हुए हैं। इस्लामी क्रांति का भारत पर बहुत कम असर पड़ा। कुछ लोगों का विचार है कि इसकी वजह अयातुल्ला खोमेनी का भारत के प्रति विशेष लगाव था क्योंकि उनके पूर्वज कभी लखनऊ में रहा करते थे।

अमरीका इस्लामी ईरान को क्षेत्र में सबसे बड़ा खतरा मानता है तथा उसे संदेह है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, हालांकि ईरान एन. पी. टी. संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है। ईरान की ऐसी छवि का भारत पर असर नहीं पड़ा जो आज अपने पुराने पड़ोसी के साथ नये संबंध बनाने की ड्योढ़ी पर खड़ा है। दोनों देशों के एक दूसरे के तरफ बढ़ने के बारे में अपनी-अपनी मजबूरियां रही हैं। ईरान भारत के अमरीकी खेमे में चले जाने को लेकर चिंतित था। वे पाकिस्तान द्वारा शिया अफगान मुजाहिदीन के विरुद्ध संघर्ष में अफगानी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार का समर्थन किये जाने से नाखुश थे। पाकिस्तान और ईरान के बीच की धार्मिक राजनीति भी इसका एक कारण थी। हाल के वर्षों में पाकिस्तान में सुन्नी कट्टरवाद के पनपने से शिया समुदाय को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिणी सोवियत संघ में स्वतंत्र गणराज्यों के उदय से भी नयी समस्याएं उठ खड़ी हुईं। ईरान का डर धार्मिक नहीं बल्कि भौगोलिक है। वह जानता है कि वह अकेले इस क्षेत्र को ईरान समर्थक या तटस्थ भी नहीं बना सकता है। इसलिए उसने भारत की मदद चाही जिसकी तटस्थता पर उसे अब भी विश्वास है।

ईरान की तरफ हाथ बढ़ाने की भारत की भी कुछ मजबूरियां हैं। ईरान एक बड़ा, तेल से समृद्ध और भारत के अत्यंत निकट का देश है। उसके साथ अच्छे संबंधों से भारत को पूरे खाड़ी क्षेत्र में एक अच्छी शक्ति प्राप्त हो जायेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी, श्रमशक्ति और वस्तुओं को न केवल ईरान में बल्कि मध्य एशिया में मुनाफे का बाजार उपलब्ध हो जायेगा। ईरान के भूतपूर्व शाह भारत और ईरान के बीच महत्वाकांक्षी सामरिक, आर्थिक संबंध बनाने के इच्छुक थे। श्री राव की हाल की यात्रा भी 1974 की इंदिरा गांधी की नये रास्ते खोलने की यात्रा के समान है। उस समय की तरह इस बार भी सामरिक और आर्थिक सहयोग तथा क्षेत्रीय पारगमन संपर्क विकसित करने पर जोर दिया गया है। **आज दोनों देशों के सुरक्षा मापदंड अधिक मर्यादित हैं। महाशक्तियों की होड़ से अब उनकी सुरक्षा को खतरा नहीं रहा लेकिन विश्व पुलिसमैन की भूमिका निभाने में लगे अमरीका के हस्तक्षेप की आशंका बनी हुई है। 1991 के खाड़ी युद्ध का सबक दोनों देशों के जेहन में ताजा है। इससे अधिक, अमरीकी प्रशासन का मानवाधिकारों पर विशेष जोर देना ईरान और भारत के लिए एक और चिंता का विषय है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन को बहाना बनाकर अमरीका कहीं दखलंदाजी न कर दे।** अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सम्मेलन की तैयारियों के लिए बैंकाक में हुई बैठक में भारत और ईरान को मानवाधिकार मसले पर एकजुट होकर काम करते देखा गया।

1970 के दशक में भारत के खनिज संसाधनों ने ईरान के शाह रजा पहलवी को आकर्षित किया। 68 करोड़ डालर की कुदरेमुख लौह अयस्क परियोजना उस समय किये गये करारों में प्रमुख थी। ईरान से सिंगापुर तक फैले एशियाई साझा बाजार की शाह की परिकल्पना के तहत ही वह भारत से सहयोग करना चाहते थे। 1974 में ईरान के शाह ने दक्षिण पश्चिम एशिया रेल संपर्क स्थापित करने का विचार रखा था। उस समय 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य होने लगे थे। लेकिन इसकी प्रक्रिया में तेजी नहीं आ पायी क्योंकि पाकिस्तानी शासक ईरान को भारतीय वस्तुओं के पारगमन के लिए मौजूदा रेल और सड़क संपर्कों को संस्थागत रूप देने के विरुद्ध थे।

पाकिस्तान इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग की प्रगति में अभी भी बाधक बना हुआ है। ईरान के क्वेशम से गैस आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव अधर में लटका है। जमीन के ऊपर बिछायी जाने वाली पाइपलाइन पाकिस्तान होकर ही बन सकती है। समुद्र के अन्दर बिछाने पर भी उसे पाकिस्तान से हमेशा खतरा बना रहेगा। इस पाइपलाइन से कराची को फायदा पहुँचाने की बात इस परियोजना में सहयोग करने के लिए पाकिस्तान को तैयार कर सकती है। लेकिन जैसा कि 1970 के दशक में देखा जा चुका है इस सन्दर्भ में पाकिस्तान पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान के सामरिक और आर्थिक हितों को लाभ भारत के साथ स्वतंत्र और निकट समीकरण बैठाने में है। भारत और ईरान के संबंध सामरिक शून्य में फलफूल नहीं सकते। विश्व के बारे में दोनों देशों के अपने विचार और भूमिका है। अमरीका, जो ईरान और इराक का एक दूसरे के विरुद्ध इस्तेमाल किया करता था, अब दोनों को क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के लिए खतरा मानता है। ईरान सोचता है कि उसे मध्य एशियाई गणराज्यों पर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव बनाना चाहिए तभी वह क्षेत्र में प्रमुख सामरिक शक्ति के रूप में उभरेगा। वह दिखाना चाहता है कि उसको शामिल किये बिना क्षेत्र में तब तक स्थायित्व लाने की कोई व्यवस्था सफल नहीं हो सकती।

भारतीय प्रधान मंत्री की ईरान यात्रा

भारत अपनी पश्चिम एशिया नीति को एक नयी दृष्टि देना चाहता है लेकिन ऐसा करते वक्त उसे शेष इस्लामी देशों की भावनाओं को ध्यान में रखना होगा। भारत का प्राथमिक उद्देश्य इस्लामी विश्व में ईरान को अपना संभाषी बनाना है लेकिन इसके लिए अभी इस्लामी सम्मेलन संगठन की अगली बैठक का इंतजार करना होगा। इस संगठन के महासचिव कश्मीर में मानवाधिकारों को एक मसला बना चुके हैं। ईरान ने इस संगठन में कश्मीर मुद्दे पर अभी तक भारत का समर्थन नहीं किया है। जहां तक श्री राव की यात्रा की उपलब्धियों का सवाल है, इस बात की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि यात्रा के अंत में जारी संयुक्त विज्ञप्ति में पाकिस्तान अथवा कश्मीर मसले का सीधा उल्लेख नहीं है।

भारतीय प्रधानमंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव की 20 सितंबर, 1993 से ईरान की तीन दिन की यात्रा से दोनों देशों के बीच मजबूत मित्रता की शुरुआत हुई है। भारत और ईरान के आपसी संबंध यद्यपि सद्भावपूर्ण रहे हैं लेकिन उनमें ठोस आधार का अभाव था। अब आपसी तथा क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के विशेष समझौते करके इस

अभाव को मिटाया जा रहा है। भारत और ईरान में आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की भावना हमेशा विद्यमान रही। चाहे शीतयुद्ध का दौर रहा हो या सोवियत संघ के टूटने के बाद के दो वर्ष का समय, भारत के नीति निर्धारक सामरिक दृष्टिकोण से ईरान के महत्व तथा दोनों देशों के बीच पारस्परिक लाभप्रद आर्थिक सहयोग की संभावनाओं को हमेशा ध्यान में रखे रहे। लेकिन जो कुछ होना चाहिए विभिन्न कारणों से वैसा हो नहीं सका।

श्री राव ने अपनी यात्रा के दौरान ईरान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक बातचीत की। यात्रा के अंत में जारी संयुक्त विज्ञप्ति तथा तेहरान में हुए समझौतों से यह कहना अनुचित नहीं होगा कि एक तरह से दोनों देशों ने एक दूसरे को खोज निकाला है। श्री राव 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान की यात्रा करने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। भारत में ईरान के राजदूत अली राजर के अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे को पहले से बेहतर ढंग से समझना शुरू कर दिया है तथा दोनों में एक दूसरे के मामले में अधिक परिपक्वता और व्यावहारिकता आ गयी है। इस यात्रा के दौरान भारत-पाकिस्तान संबंधों, विशेषकर कश्मीर का मामला उठा। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है ईरानी नेताओं की तरफ से भारत विरोधी रुख होने का कोई संकेत दिखायी नहीं दिया। कश्मीर को भारत के आंतरिक मामले के रूप में स्वीकार करने के बारे में ईरानी नेताओं का रुख सकारात्मक है। दोनों देशों के मध्य हुए समझौते मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा नये मध्य एशियाई स्वतंत्र गणराज्यों के साथ भारत के व्यापार के लिए परिवहन तथा पारगमन सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित हैं। जहां ईरान भारतीय प्रौद्योगिकी चाहता है, वहीं भारतीय निर्यातक मध्य एशियाई बाजार का लाभ तभी उठा सकते हैं जब ईरान भारतीय माल की आवाजाही को अनुमति प्रदान कर दे। ईरान ने अपने बंदर अब्बास बंदरगाह से मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए मार्ग उपलब्ध कराने की पेशकश की है। भारत और इन गणराज्यों के बीच मौजूदा मार्ग काफ़ी लंबा है। इन गणराज्यों में से अधिकांश भारतीय वस्तुओं से अवगत हैं और अपना आयात जारी रखने के इच्छुक हैं। ईरान होकर इन गणराज्यों तक रेल संपर्क पूरा हो जाने पर इन क्षेत्रों में पहुँचना बहुत आसान हो जायेगा। आर्थिक सहयोग की सूची में व्यापार के साथ-साथ कई अन्य विषय शामिल हैं। इस समय भारत ईरान से लगभग 30 लाख टन कच्चा तेल आयात करता है। भविष्य में इसके और बढ़ने की संभावना है। ईरान से भारत तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के बारे में जुलाई 1993 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। इस संबंध में विस्तृत संभावना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

परियोजनाएं

भारत की कई सरकारी और गैर सरकारी कंपनियाँ ईरान में परियोजनाएं चला रही हैं। इनमें सबसे बड़ी परियोजना कर्मान प्रांत में है। 60 करोड़ डालर लागत वाली इस परियोजना में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मुख्य भागीदार है। दो भारतीय कंपनियों ने कुजेस्तान की 25 करोड़ डालर की चीनी मिल परियोजना के लिए टेंडर भरे हैं। राइट्स तथा टाटा कंसलटेंसी कुछ परामर्शदात्री परियोजनाएं चला रही हैं, वहीं भारत की कुछ प्रमुख सीमेंट कंपनियाँ ईरान के सीमेंट कारखानों का आधुनिकीकरण करने की संभावनाओं का पता लगा रही हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को तेहरान मेट्रो वर्कशाप को उपकरण और वाहन की आपूर्ति करने का साढ़े चार करोड़ डालर के तथा राइट्स को 4.7 करोड़ डालर की अहवाज-बंदेरीमान परियोजना का आदेश मिला है। सरकारी सूत्रों के अनुसार निकट भविष्य में ईरान के साथ कुल मिलाकर लगभग एक अरब डालर मूल्य की परियोजनाओं के संबंध में करार होने की आशा है।

व्यापार

ईरान को निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं में चाय, काफी, साइकिलों तथा वाहनों के पुर्जे और चमड़े की वस्तुएं हैं। ईरान को भारत का निर्यात 1991-92 में 300 करोड़ रुपये तथा 1992-93 में 328 करोड़ रुपये का था जबकि इन दोनों वर्ष में भारत का आयात क्रमशः 1435 करोड़ रुपये और 1149 करोड़ रुपए था। दोनों देशों के दो संयुक्त उद्यम इस समय कार्य कर रहे हैं। ये हैं- ईरान में ईरानी-हिंद शिपिंग कंपनी तथा भारत में मद्रास फर्टिलाइजर्स और मद्रास रिफाइनरीज।

समझौते

भारत और ईरान ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने तथा मध्य एशियाई क्षेत्र के साथ आर्थिक और व्यावसायिक संपर्क बढ़ाने, सुविधाएँ विकसित करने में सहयोग देने पर जोर दिया गया है। भूतल परिवहन तथा पारगमन सुविधाओं से संबंधित समझौते पर भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री रघुनंदन लाल भाटिया तथा ईरान के विदेश मंत्री अली अकबर विलायती ने हस्ताक्षर किए। दोनों देश मध्य एशियाई क्षेत्र में आर्थिक संबंध बढ़ाने के भारत और ईरान की मौजूदा सड़कों, रेल लाइनों तथा बंदरगाहों की सुविधाओं के उपयोग की संभावनाओं की ओर जांच करने पर सहमत हुए तथा मामले का अध्ययन के लिए विशेषज्ञ दल एक दूसरे के यहां भेजेंगे। दोनों पक्षों ने महसूस किया कि मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाकर ईरान के रास्ते मध्य एशिया के साथ पारगमन व्यापार हो सकता है। भारतीय पक्ष ने इस संबंध में ईरान द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौते के अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में आपसी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने पर सहमत हुए। दोनों देश एक दूसरे पर वैज्ञानिक-तकनीकी सूचनाएं, पुस्तकें तथा अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे, वैज्ञानिक प्रतिनिधिमंडलों को एक दूसरे के यहाँ भेजेंगे तथा आपसी हित से जुड़ी समस्याओं पर द्विपक्षीय वैज्ञानिक और तकनीकी संगोष्ठियां तथा सम्मेलन आयोजित किये जाएंगे।

परिवहन और पारगमन के बारे में हुआ समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इसका भारत और ईरान के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के साथ-साथ मध्य एशियाई देशों के साथ दोनों के संबंधों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। दोनों सरकारों ने ईरान के रास्ते मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गत जुलाई में ईरान का दौरा करने वाले भारत के तकनीकी दल की रिपोर्ट पर विचार किया है। इस दल ने पारगमन सुविधाओं के लिए बंदर अब्बास को सबसे उचित बंदरगाह बताया है। ईरान ने बंदर अब्बास से तुर्कमेनिस्तान तक सड़क बनायी है तथा दोनों ओर से लगभग 300 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछायी जा रही है जिसका काम शीघ्र ही पूरा हो जायेगा।

कश्मीर

ईरान ने भारत को स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि वह कश्मीरी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ईरान कश्मीर मसले को भारत का आंतरिक मामला मानता है। श्री राव ने कहा कि इस मसले पर ईरानी नेताओं का रुख सकारात्मक है। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा को लाभप्रद बताया और कहा कि ईरानी राष्ट्रपति तथा अन्य नेताओं के साथ उनकी बातचीत बहुत सद्भावपूर्ण रही।